Carbon Market Watch

#4 December 2012

पारखी नज़र

कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की विचारधाराएँ

सम्पादकीय

हमारे एन जी ओ की पत्रिका "पारखी नज़र! कार्बन बाज़ार पर एन जी ओ की आवाज़"के सी ओ पी के बाद के संस्करण में आपका स्वागत है!

सी ओ पी 18 दोहा (COP18 in Doha) में देशों ने कई बिलियन टन की उस दरार को जिसे कि हमें मौसम के भीषण दुष्प्रभावों से बचने के लिए भरना ज़रूरी है उसे सम्बोधित करने के लिए कुछ खास नहीं किया। कम करने की कोई नई प्रतिज्ञाएँ नहीं ली गई और जो व्याप्त लूपहोल हैं वे भी जस के तस रहे। इसके बाद भी कई सकारात्मक निर्णय लिए गए: पार्टियों ने इस बात पर सहमति दी कि अगले कोयोटो प्रतिबद्धता की आवधि में कोई नई गर्म हवा का उत्पादन न हो व प्रतिबद्धता की पहली आवधि में से भी केवल सीमित माता में ही गर्म हवा का उपयोग किया जाए। इसके साथ ही दोहा में लिए गए निर्णयों से कहीं भी यह सुनिश्चित नहीं हुआ कि दुनिया गर्म होने के तापमान से 2 डिग्री कम रहेगी, कार्बन बाज़ार बढ़ते रहेंगे व सामान्य नियमों की कमी बनी रहेगी। हमें एक साथ मिलकर काम करते रहना होगा ताकि हम निरंतर दवाव बनाकर रखें कि वास्तविक समाधान हों और हम तब तक लड़ाई जारी रखें जब तक खराब प्रोजेक्ट व योजनाएँ दूर न हों।

इस संस्करण में ओ सी ओ पी 18 के विषय में, पोकर का जो खेल हमने टाइटेनिक में जीता व क्यों सी डी एम पर लिए गए गलत निर्णय अच्छा समाचार हो सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी विशेष फाइल में आप सी ओ पी 18 व दुनिया भर के कार्बन बाज़ारों जिसमें आर ई डी डी पर टिप्पणी भी शामिल होगी, मिट्टी कार्बन बाज़ार व बाज़ार की नई प्रणालियों के विषय में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। आप यह भी जानेंगे कि क्यों भद्र समाज को खेती की सौदेबाज़ी में सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको मेक्सिको के समस्या ग्रस्त हवा चालित प्रोजेक्टों की जानकारी भी प्राप्त होगी व दक्षिण अफ्रीका के बदनाम बिसासर सड़क गढ्ढे भराव प्रोजेक्ट की भी।

पारखी नज़र! कार्बन बाज़ार पर एन जी ओ की आवाज़ एक त्रैमासिक पत्रिका है जो कि अंग्रेज़ी, स्पैनिश और हिन्दी में अभियान की नवीनतम जानकारी व दुनिया भर के विचारों के साथ उपलब्ध है। यदि आप **पारखी नज़र!** के अगले संस्करण में योगदान करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई टिप्पणी हैं तो कृप्या निम्न पर सम्पर्क करें

antonia.vorner@carbonmarketwatch.org

विषय वस्तु

page 2. सी ओ पी 18 का सार - हमने टाइटेनिक पर सवार होकर पोकर का खेल जीता!

page 4. जब किसान भूखे हों तब कार्बन के साथ छेड़छाड़

page 6. सी ओ पी 18 में कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़

page 11. मेक्सिको में हवा की ऊर्जा को काम में लाने की चुनौती - इस्थमस ऑफ त्यूहैनटेपैक का केस

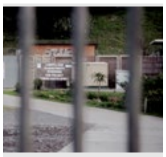

page 13. बिसासर सड़क के गढ्ढे भराव का प्रोजेक्ट: पर्यावरण के लिए खतरा

पारखी नज़र! सूचनापट्ट

हमारी नई वेबसाइट को देखें!
पारखी नज़र वालों के नेटवर्क से जुड़ें!
हमारा सी ओ पी 18 में काम देखें!

page. 15

सी ओ पी 18 का सार - हमने टाइटेनिक पर सवार होकर पोकर का खेल जीता!

ईवा फिल्ज़मोज़र,
डायरेक्टर कार्बन मार्केट वॉच

हमें इस बात का बहुत खेद है कि जो देश सी ओ पी 18 दोहा में मिले उन्होंने कई बिलियन टन की दरार को जिसे कि हमें मौसम के भीषण दुष्प्रभावों से बचने के लिए भरना ज़रूरी है उसे सम्बोधित करने के लिए कुछ खास नहीं किया। जहाँ पर्यावरणविदों व संवेदनशील देशों के प्रतिनिधियों ने हमारे संसार के भविष्य के विषय में अपनी चिंताएँ प्रकट कीं, वहीं कार्बन बाज़ार के उद्योगों को केवल भविष्य में कार्बन के दामों की चिंता थी जो कि इस समय न्यूनतम दर 50 सेन्ट प्रति टन कार्बन डाय ऑक्साइड पर है। इनमें से किसी भी समस्या का निवारण नहीं किया जा सका। फिर भी कार्बन बाज़ारों (डूबते हुए जहाज) पर कुछ सकारात्मक निर्णय लिए गए।

2013 और 2020 के बीच में कार्बन केडिटों की भारी मात्रा के सम्बन्ध में क्या किया जाए यह चुनौती पहले भी थी और अब भी बनी हुई है। हालांकि इसका तर्कसंगत निर्णय यह होना चाहिए कि महत्वाकांक्षा को बढ़ाया जाए और कल्पनाशील तरीकों के प्रयोग से किस प्रकार कार्बन के दामों में बढोत्तरी की जाए इस पर चर्चा हुई। कई सेशनों के पश्चात जिसमें कि एक कार्बन बाज़ारों का उच्च स्तरीय भाग भी शामिल था उसने इस बात पर विचार विमर्श किया कि सी डी एम के 4 गीगाटन अतिरिक्त कार्बन केडिटों व 13 गीगाटन गर्म हवा के स्रावों के अतिरिक्त पर्मिट (ए ए यू) जो इन्टरनैशनल एमिशन ट्रेडिंग द्वारा जारी किए गए थे उनका क्या किया जाए। भारत ने एक स्टैबिलाइज़ेशन फन्ड जो कि अतिरिक्त सी डी एम केडिट खरीदे, उसे बनाने का सुझाव दिया, न्यूज़ीलैंड ने कोयोटो प्रोटोकॉल प्रणालियों पर सबको आ सकने की सुविधा के लिए कहा। कार्बन मार्केट वॉच पार्टियों का हाथ उठा कर इन दोनों प्रस्तावों से इन्कार करने के लिए अभिवादन करती है परन्तु उसे इस बात का खेद है कि सी डी एम की मूलभूत कमियों को सम्बोधित करने के लिए राजनैतिक इच्छा की कमी है।

दोहा - सी डी एम का अन्त?

सी डी एम के भविष्य को लेकर सी ओ पी 18 में जो समझौता वार्ता हुई उसकी शुरूआत कुछ अच्छे विकल्पों के साथ हुई जो कि चेयरमैन के अन्तिम निर्णय के लिए आधार थे। हालांकि सी डी एम की चर्चाओं के दौरान लगातार इस बातचीत के ड्राफ्ट का मसौदा कमज़ोर पड़ता गया व उन चिंताओं के विषय को सम्बोधित नहीं किया जिनको वैज्ञानिकों ने बार बार प्रमुखता दी थी। उदाहरण के लिए सी डी एम की योजना अनुसंधान टीम की खोज ने दिखाया है कि विशाल स्तर के सी डी एम के पावर प्रोजेक्टों (जैसे कि कोयला व हायड्रो पावर प्रोजेक्ट) अधिकतर गैर अतिरिक्त होते हैं व इसलिए इनसे ग्लोबल स्रावों में बढोत्तरी होती है। 2020 तक सी डी एम के आधे से ज़्यादा केडिट इन्हीं प्रोजेक्टों से मिलने के बावजूद आपूर्ति व गुणवत्ता के विकल्पों के कारण इन नकली कार्बन केडिटों को सिस्टम में आने देने से रोकने के लिए इनके बारे में विचार किया ही नहीं गया। इसके स्थान पर अन्तिम निर्णय में ज़्यादा लचीलापन है व अतिरिक्तता का परीक्षण भी ज़्यादा कठोर है। सुझाए गए अन्य सुधार जैसे कि किसी भी पार्टी के स्वीकृति पत्र से हाथ खींच लेने के परिणाम व ऑडिटरों की जवाबदेही के तरीकों को अन्तिम वक्तव्य से हटा दिया गया। सी डी एम प्रोजेक्टों के दीर्घ कालिक विकास को बढ़ावा देने के सुझावों को भी नामंजूर कर दिया गया। एक मुख्य निर्णय था सी डी एम के तरीकों व प्रणालियों का सम्पूर्ण पुनरीक्षण जो कि वर्ष 2013 के दौरान किया जाएगा। हालांकि सी डी एम

परन्तु सी ओ पी 18 में लिए गए निर्णयों को सकारात्मक तरीके से भी देखा जा सकता है। सबसे पहले सी डी एम के नियमों को लागू करना जो कि दोहा में तय किया गया था से अनुमान है कि बाज़ार का भट्टा बैठ जाएगा और इससे यह साबित हो जाएगा कि कमज़ोर नियम जो कि अधिक कार्बन केडिटों को बढ़ावा देते हैं उनसे बाज़ार को बचाया नहीं जा सकता। महत्वाकांक्षी व बाँध कर रखने वाले प्रोजेक्ट और अच्छे गुणों वाले नियम व राजनैतिक इच्छा ही यह सब ला सकती है।

की गुणवत्ता के मुद्दे के खिलाफ राजनैतिक अनिच्छा व वर्तमान 4 गीगाटन की कार्बन डाय ऑक्साइड की अतिरिक्त आपूर्ति को देखते हुए यह सोचना कठिन है कि यह पुनरीक्षण सी डी एम को कैसे बचा पाएगा। कार्बन का बाज़ार भाव 50 सेन्ट प्रति टन कार्बन डाय ऑक्साइड होने से ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा जो दूर दूर तक भी अतिरिक्त नहीं होगा। इसका नतीजा और भी कम गुणवत्ता वाले क्रेडिटों से बाज़ार का भरना होगा और स्राव भी कम नहीं होंगे।

परन्तु सी ओ पी 18 में लिए गए निर्णयों को सकारात्मक तरीके से भी देखा जा सकता है। सबसे पहले सी डी एम के नियमों को लागू करना जो कि दोहा में तय किया गया था से अनुमान है कि बाज़ार का भट्टा बैठ जाएगा और इससे यह साबित हो जाएगा कि कमज़ोर नियम जो कि अधिक कार्बन क्रेडिटों को बढ़ावा देते हैं उनसे बाज़ार को बचाया नहीं जा सकता। महत्वाकांक्षी व बाँध कर रखने वाले प्रोजेक्ट और अच्छे गुणों वाले नियम व राजनैतिक इच्छा ही यह सब ला सकती है। सी डी एम का अन्तिम निर्णय आप यहाँ **here** देख सकते हैं।

और अब अच्छी खबर: बाज़ार की नई प्रणालियों को टाल दिया गया, ए ए यू को रोका गया

इस समय के लिए हम अपनी चिंताओं को वर्तमान प्रणालियों पर केन्द्रित रख सकते हैं। दो "नए बाज़ार" पर आधारित प्रोग्रामों न्यू मार्केट मेकेनिज़म (एन एम एम) व फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस अप्रोचेज़ (एफ वी ए) जिनमें कि बाज़ार पर आधारित उपकरण भी आते हैं उन पर लिए गए निर्णयों को अगले वर्ष तक के लिए टाल दिया गया। आप एन एम एम व एफ वी ए के विषय में हमारे सी ओ पी 18 सार में पढ़ सकते हैं जो कि जल्दी ही यहाँ here प्रकाशित किया जाएगा।

पार्टियों के द्वारा जॉइन्ट पोलिटिकल विल को दोहा में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सफलता मिली: कोयोटो प्रोटो कॉल की पहली प्रतिबद्धता आवधि (2008 से 2012) के अन्तर्गत 13 बिलियन अतिरिक्त भत्तों (ए ए यू) में से अधिकतर को रोक दिया जाएगा। कायोटो प्रोटोकॉल में नवीनतम संशोधन के अनुसार नई उत्पादित गर्म हवा को 2012 में सीमित किया जाएगा और 2020 के कुछ पार्टियों के कमज़ोर लक्ष्यों में संशोधन होगा।

यह भी एक अच्छी खबर है कि कोयोटो पार्टियों को 2014 तक अपने 2020 के लक्ष्यों का पुनरीक्षण करना होगा ताकि वह कमी की 2020 तक आई पी सी सी की चौथी विश्लेषण रिपोर्ट में 25 से 40 प्रतिशत की सीमा से तुलनात्मक हो सकें। मौसम का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता अन्तत: पार्टियों द्वारा सी ओ पी से पहले किए गए गृहकार्य पर निर्भर होता है। अब लम्बी छुट्टियों के लिए समय नहीं है, चलिए मिलकर अपनी सरकारों को कहते रहते हैं कि वे अपनी कमर कस लें और हमारे संसार को बचाएँ!

पुनरीक्षक संस्थाएँ सी डी एम सुधारों, जे आई, आर ई डी डी, एन एम एम व एफ वी ए पर अपनी टिप्पणियाँ यू एन एफ सी सी सी को 25 मार्च 2013 तक दे सकती हैं।

आर ई डी डी पर दोहा में गतिरोध

गैर सुलझे हुए मुद्दों पर अलग अलग विचार होने के कारण यू एन एफ सी सी सी के तहत वनों को सम्बोधित करने की प्रकिया दोहा में रूक गई और आगे न बढ़ सकी। यू एन एफ सी सी सी की एक सहायक संस्था एस बी एस टी ए के साथ अगले साल बातचीत जारी रहेगी व इन चर्चाओं में कार्बन बाज़ार का विषय गर्म रहेगा। कई पुनरीक्षक व कुछ देश जैसे कि बोलिविया ने आर ई डी डी को कार्बन व्यापार की प्रणाली की तरह उपयोग करने का विरोध किया है परन्तु कई अन्य इसे आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि वे ऑफसेटों को एक वित्तीय आधार की तरह देखते हैं। बॉन में यह परिचर्चा जारी रहेगी और हम इसको ध्यापूर्वक देखते भी रहेंगे।

आर ई डी डी
(रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डीफॉरेस्टेशन एन्ड डीग्रेडेशन)

युनाइटेड नेशन की एक प्रणाली है जो कि विकासशील देशों को बढ़ावा देती है कि वे वनों के काटने व वनों की गुणवत्ता कम होने से होने वालों स्रावों में कमी लाएँ। महत्वपूर्ण निर्णयों को 2013 व उसके बाद होने वाली चर्चाओं के लिए टाल दिया गया है। एक बार फिर आर ई डी डी को आर्थिक मदद कैसे मिले इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया पर प्रतिनिधियों ने एक कार्य के कार्यक्रम work programme को तैयार किया है जिसपर सी ओ पी 19 में अगले वर्ष निर्णय लेने की तैयारी है। आर ई डी डी के प्रोजेक्टों को आर्थिक सहायता देने के लिए सुझाव 25 मार्च 2013 तक आमन्त्रित किए गए हैं जिसमें कार्बन के बिल्कुल प्रयोग न करने पर लाभ जैसे कि बायोडाइवसिर्टी को बढ़ाना शामिल हैं। बॉन में जून 2013 में इस विषय में पहली कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। आप सी ओ पी 18 में आर ई डी डी के विषय में यहाँ पर here और here अधिक जानकारी पढ़ सकते हैं।

जब किसान भूखे हों तब कार्बन के साथ छेड़छाड़?

अनिका श्रोडर, पॉलिसी ऑफिसर फॉर क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डेवेलपमेन्ट, मिसरीओर

नए अध्ययनों से पता चला है कि खेती बहुत कम दाम के स्रावों में कमी लाने की भावी आशंका की पहचान करके कमी लाने व उसे इस क्षेत्र में ग्रहण करने का प्रयास करती है। इसके परिणाम स्वरूप खेती मौसम की चर्चाओं में तेज़ी से आ रही है। हालांकि दोहा में हाल के मौसम की परिचर्चा पर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इस क्षेत्र में कम करने के निवेशों के साथ होने वाले खतरों को देखते हुए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता था।

अधिकतर पार्टियाँ व निरीक्षक दोहा में मौसम की बातचीत के दौरान खेती पर एक कार्यक्रम की अपेक्षा कर रहे थे। अन्त में कोई समझौता नहीं हो सका व बातचीत जून में अगली यू एन मीटिंग में जारी रहेगी। यू एन एफ सी सी सी के तहत खेती के समझातों पर ध्यान अब भी बँटा हुआ है: क्या ध्यान ग्रहण करने पर, ग्रहण करने व कमी लाने पर या फिर कमी लाने व खेती में सामन्जस्य बनाने पर होना चाहिए? कई लोगों को यह बेकार लग सकता है। अफ्रीकन यूनियन को खासकर यह लगा कि यह किस प्रकार की खेती को भविष्य में यू एन एफ सी सी सी की आर्थिक मदद मिलेगी उसके बारे में है। यू एस जैसे कुछ विकसित देश "समान परन्तु अलग अलग ज़िम्मेदारी" के संदर्भ को जानबूझ कर रोक रहे थे। अफ्रीकन देशों को इस बात का भय था कि उन्हें स्रावों को कम करने की भविष्य में ज़िम्मेदारी हो जाएगी व उन्होंने केवल ग्रहण करने के लिए ही मत दिया। समुदायों को मौसम में बदलाव की आदत डालने के लिए आर्थिक मदद की कमी के कारण अन्य विकासशील देशों ने ग्रहण करने व कमी करने दोनों पर केन्द्रित रहना ही ठीक समझा क्योंकि उन्हें खेती में निवेश को तुरन्त पाने की आशा दिखाई दी।

सबसे कमज़ोर को सहायता देने के स्थान पर कार्बन को मापना?

असल में ऐसे बहुत से चलन जिनके द्वारा ज़मीन व पौधों में कार्बन की मात्रा में बढोत्तरी होती है उनसे अधिक उपज प्राप्त होती है - जैसे कि खाद प्रयोग करने से होता है। तो कमी लाने व ग्रहण करने के बीच सामंजस्य बनाने के विचार का साथ देने में क्या बुराई है?वैसे तो कोई भी नहीं परन्तु सबसे पहले कार्बन के विषय में बातचीत के इतिहास से पता लगता है कि जब भी ज़मीन के उपयोग के स्रावों की चर्चा की जाए तब काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आर ई डी डी या सी डी एम और राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत भूमि प्रयोग के कार्यो द्वारा स्राव कम करने के प्रयास गरीब किसानों व देसी समुदायों के लिए बहुत ही खराब साबित हुए हैंअपनी ज़मीन से हटने के कारण अक्सर प्राकृतिक संसाधनों जिनपर उनका रोज़गार निर्भर करता है उनके लिए किसानों का पहुँचना मुश्किल हो जाता है। दूसरे इस बात का भी गंभीर खतरा बना रहता है कि जो सीमित धन राशि विकास व ग्रहण करने के लिए उपलब्ध होती है वह खेती व उत्पादन प्रणालियों के कार्बन के हिसाबकिताव को करने के लिए चली जाएगी। तीसरा धन राशि उन प्रणालियों की मदद करेगी जो कि सबसे अधिक कार्बन अधिग्रहण के तरीकों को लाएगी और इसके लिए "सबसे सही तरीका" साबित होगी न कि किसान के लिए ज़रूरी सबसे सही सहारा। यह विशेषकर तब सबसे सही होता है जबकि खेती को कार्बन बाज़ार की स्कीमों के अन्तर्गत लाया जाता है जो कि वर्ल्ड बैंक, प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स, आस्ट्रेलिया व अन्य के द्वारा उभारी जाती है।

मिसरिओर जर्मन कैथोलिक बिशप की संस्था है जो कि सहयोग का विकास करती है। 1958 में स्थापित होने के बाद से ही इस संस्था ने किसान समुदाय जिसमें कि केवल वे लोग नहीं हैं जो कि मदद के केवल निष्क्रीय पाने वाले हैं, वरन् ये अपने जीवनयापन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं,
उनकी अपनी मदद स्वयं करने की क्षमता को मज़बूत किया है।

भद्र समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है और इस बात को फैलाने की भी कि विकासशील देशों में किसानों की मदद करने के लिए सर्वप्रथम शुरूआत मौसम में बदलाव के भयंकर परिणामों को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना। **जैसे जैसे समय निकलता जाएगा कार्बन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए समय ही नहीं बचेगा!**

कार्बन बज़ार – मौसम व लोगों के लिए अनुमान लगाने का एक खेल मात्र

कार्बन बज़ारों के द्वारा खेती को आर्थिक मदद से केवल बड़े स्तर पर खेती व उन कम्पनियों को लाभ पहुँचेगा जो कि केडिट खरीदने वालों व कार्यक्रमों की निगरानी करने वालों के ऊँचे दामों पर बातचीत कर सकते हैं। इससे बड़े स्तर पर खेती को प्रोत्साहन मिलेगा व आगे चल कर भूमि हड़पने की प्रणालियाँ भी कार्यशील होने लगेंगी। इसके साथ साथ कार्बन बाज़ार के लिए तैयार प्रोजेक्ट ज़रूर ही विकास के प्रयत्नों में से ढाँचागत, आर्थिक व मानव संसाधनों को इधर उधर ले जाएँगे क्योंकि इसके दाम का एक बड़ा हिस्सा ऑफिशियल डेवेलपमेन्ट असिस्टेन्स (ओ डी ए)के द्वारा वहन किया जाता है। एफ ए ओ के एक अनुमान के अनुसार **2010** व **2030** के बीच में करीब **17** बिलियन यूरो की आवश्यकता एक ऐसी प्रणाली को बनाने के लिए पड़ेगी जो कि कार्बन के व्यापार को भूमि कार्बन अधिग्रहण के माध्यम से बढ़ावा देगी। वर्तमान चर्चाओं में यह तथ्य की कार्बन को केवल अस्थायी रूप में ही जमा करके रखा जा सकता है गंभीरता से न लेकर ध्यान में नहीं रखा गया। इसके साथ साथ भूमि व बायोमास में होने वाली जटिल बायलौजिकल प्रकियाओं के कारण एक सही मिट्टी में कार्बन का नाप लेना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि यह कार्बन अधिग्रहण को अंकों में बताने के लिए ज़रूरी होता है ताकि फिर उसके फलस्वरूप सी ई आर दिए जा सकें। ऑफसेटिंग व अन्य व्यापार की स्कीमें जो मिट्टी व बायोमास में कार्बन अधिग्रहण करती हैं वह केवल अनुमान लगाने का एक खेल बन कर ही रह जाता है और यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तापमान में बढ़ोत्तरी के रूप में होता है व परिणाम स्वरूप कमज़ोर वर्ग पर ही बुरा असर डालता है।

कार्बन बाज़ार में खेती : दोहा में जंग का मैदान

जहाँ कि अमरीका व आस्ट्रेलिया इस बात पर डटे रहे कि वे अपने काम के कार्यक्रम की चर्चाओं में कोई अन्य छिपा हुआ एजेन्डा नहीं रखते व वे केवल "विकासशील देशों को सभी संभव सलाह व सहारा देने के लिए तैयार हैं" परन्तु यह समझ में आ गया कि वे वास्तव में खेती को बातचीत की अन्य दिशा के संदर्भ में क्या चाहते हैं। उन्होंने मिट्टी के कार्बन बाज़ार के लिए जितने संभव हों उतने दरवाज़े खोलने के लिए खूब लड़ाई की। आस्ट्रेलिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे सी डी एम में खेती के कार्यो को शामिल करना चहते हैं (सी डी एम एल यू एल यू सी एफ समझौता वार्ता में)। यह चर्चा करते समय कि भूमि कार्बन अधिग्रहण की अस्थायित्व से कैसे निपटा जाए उन्होंने एक स्टार भी अपनी प्रस्तुति submission,के लिए प्राप्त किया। इससे यह साबित हो जाता है कि अस्थायित्व का खतरा प्रोजेक्ट के मेज़बान देश पर ही रहेगा! ए डी पी के कम करने के विवरण पर भी खेती का वर्णन दिखाई दिया जिसे कि अन्तिम क्षणों में वीटो करके जी 77 द्वारा हटा दिया गया। हालांकि फिर भी एक अप्रत्यक्ष संदर्भ बचा रहा क्योंकि ए डी पी ADP भविष्य में विषयक कार्यशालाएँ व प्रस्तुतियाँ करना चाहता है जिनसे उन पहलों व विकल्पों के बारे में पता लग सके जो महत्वाकांक्षा को बढ़ाएँ व "कम करने और ग्रहण करने के लाभों को दिलाएँ जिसमें कि मौसम में बदलाव के प्रति लचीलापन आ सके" जो कि खेती के स्पष्ट संदर्भ में है। दुर्भाग्यवश कार्बन बाज़ारों की लॉबी की ही अन्त में जीत हुई और भूमि प्रयोग के कार्य अब बाज़ार की नई प्रणाली का हिस्सा होंगे जैसा कि agreed outcome pursuant to the Bali Action Plan में कहा गया है और जिसमें कि कार्बन का लेखा जेखा (एम आर वी) "निकाला जाना" शामिल है।

भद्र समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है व उन्हें अफ्रीकी यूनियन के लिए आवाज़ उठानी है कि विकासशील देशों के किसानों की मदद के लिए सर्वप्रथम कदम मौसम में बदलाव के गम्भीर प्रभावों को ग्रहण करने को बढ़ावा देना होना चाहिए! जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे कार्बन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए समय ही नहीं बचेगा!

पढ़ने के लिए अन्य सामग्री व संदर्भ:

खेती के संदर्भ में मौसम की योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त व सुझाव Agriculture: from Problem to Solution Achieving the Right to Food in a Climate-Constrained World. Guiding Principles and Recommendations. CIDSE 2012

MISEREOR 2012: "Climate-smart agriculture – A useful development paradigm?"

MISEREOR 2012: "Carbon markets in Agriculture – Benefitting the Poor and the Climate?" http://www.misereor.org/publications/climate-change-and-justice.html

सी ओ पी 18 में कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज

खेती के कार्बन बाज़ार - खाद्य सुरक्षा को बेचना

टेरेसा एन्डरसन, जी ए आई ए फाउन्डेशन की इन्टरनैशनल एडवोकेसी कोऑरडिनेटर

दोहा में सी ओ पी 18 में कार्बन बाज़ारों ने मौसम के हरेक क्षेत्र में अपना निदर्यी फैलाव जारी रखा जिसमें खेती भी शामिल था। स्रावों को कम करने की अत्यधिक राजनैतिक परिचर्चाओं में यू एन एफ सी सी सी की हरेक समझौता वार्ता में लूप होल व कार्बन बाज़ार दिखाई दिए। अफ्रीकी व जी 77 देशों ने खेती की चर्चाओं को खाद्य सुरक्षा व ग्रहण करने के लिए तुरन्त व ज़रूरी कदम उठाने पर केन्द्रित होने की गुहार लगाई। हालांकि ई यू, यू एस व नयूजीलैंड ने कम करने की भाषा पर बल दिया जिसके कारण खेती विकसित देशों के कार्बन बाज़ारों में आ सकती है।

इस गतिरोध का नतीजा यह हुआ कि खेती पर कोई समझौता न हो सका। इसलिए अगले साल एस बी एस टी ए में यह लड़ाई जारी रहेगी। इसी तरह भूमि के प्रयोग पर चर्चाएँ, भूमि प्रयोग में बदलाव व फॉरेस्ट्री (एल यू एल यू सी एफ) कि क्या "अस्थायी" (जैसे कि खेती) कार्बन केडिटों को सी डी एम में शामिल करना चाहिए या नहीं पर भी निर्णय नहीं लिया जा सका और ये अगले वर्ष फिर से सामने आएँगे।

हालांकि बाज़ार की नई प्रणालियों के बारे में चर्चा में खेती को स्पष्ट रूप से कार्बन बाज़ारों से जोड़ा गया। एक अध्ययन व कार्यशाला के लिए एक निवेदन किया गया जो कार्बन को हवा में से भूमि पर आधारित तरीकों जेसे खेती के द्वारा हटाने के मुद्दे की जॉच, परीक्षण व रिपोर्टिंग के लिए था। जैसे कि ई यू के एक मध्यस्थ ने मुझसे खेद प्रकट करते हुए कहा कि "मुझे यह बोध हो रहा है कि मेरे साथी ई यू के लोगों का एक मात्र ख्याल केवल मौसम के बदलाव को सामने लाना और कार्बन का मोल लगाना है"

ई यू के एक मध्यस्थ ने मुझसे खेद प्रकट करते हुए कहा कि "मुझे यह बोध हो रहा है कि मेरे साथी ई यू के लोगों का एक मात्र ख्याल केवल मौसम के बदलाव को सामने लाना और कार्बन का मोल लगाना है"

क्या सी ओ पी 18 ने वनों को आफसेट में बदलने के लिए कोई पीछे का दरवाज़ा खोल दिया है?

सिबेस्टियन बॉक, कैम्पेनर (फॉरेस्ट एन्ड क्लाइमेट पॉलिसीज़), ग्रीन पीस इन्टरनैशनल

वनों के संदर्भ में दोहा में उस प्रकिया का अन्त हुआ जो कि बाली में आरम्भ हुई थी, जहॉ पर विकसित देशों ने ट्रॉपिकल वनों वाले देशों की आर्थिक मदद करना तय किया था वनों के कटान व उनके नष्ट होने (आर ई डी डी) के एवज़ में। जबकि आर ई डी डी के साथ नहीं के बराबर प्रगति हुई, दोहा में सी ओ पी 18 के अन्तिम घंटों में एक भानुमति का पिटारा खुल गया जिसके कारण वनों को आफसेट में कार्बन बाज़ार में एक अनुपालन विकल्प के रूप में परिवर्तित किया जा सकता था।

इस प्रयास में कि कोयोटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता आवधि को जीवित रखा जा सके, अन्तिम क्षणों में इस बात को शामिल किया गया कि यू एन एफ सी सी (और शायद कहीं अन्य भी) द्वारा विकसित बाज़ार प्रणलियों के "कोई भी" कारकों का प्रयोग विकसित देशों के स्रावों की भरपाई करने के लिए किया जा सकता है। नए वर्णन के अनुसार इस बात की अनुमति है कि "कोई भी" कारक जो कि बाज़ार पर आधारित प्रणाली में कन्वेन्शन के तहत तय किए गए हों या उनके उपकरण का प्रयोग पार्टियों के द्वारा अनेक्सचर 1 में उन्हें यह बात मानने में कि स्रावों को सीमित करने की संख्या व आर्टिकल 3 के तहत कम करने की प्रतिबद्धता को शामिल किया जा सकता है। जहॉं कि कुछ पार्टियॉं यह चिन्हित करने में जल्दी मचा रही थीं कि आर ई डी डी के तहत बाज़ार पर आधारित प्रणालियों के नियम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं, अन्य कई देश इस तरह के बज़ार के पैरवी कर रहे थे। नई भाषा को शामिल करने के साथ साथ इस बात का भी खतरा है कि आर ई डी डी के क्रेडिटों को पिछले दरवाज़े से अनुमति मिल जाए उस ऑफसेट की तरह जो कि अनुपालन की तरह माना जाएगा।

कई वर्षों से ग्रीन पीस व अन्य इस बात के विषय में खुल कर बोल रहे हैं कि हमें मौसम परिवर्तन को रोकने के लिए एक वास्तविक अवसर दिया जाना चाहिए, हमें वन कटान व औद्योगिक स्रावों दोनों को सही करने की आवश्यकता है। बार बार वनों को ऑफसेट की तरह प्रयोग होने देने से इस नए वर्णन में एक का दूसरे के स्थान पर आ जाने का खतरा है। हालांकि अन्तिम समय में किए गए इस बदलाव का क्या प्रभाव होगा वह अभी अस्पष्ट ही है, परन्तु यह चिंता का विषय ही है कि यह आर ई डी डी के कुछ भागों को ऑफसेट स्कीम में परिवर्तित न कर दे।

"सी ओ पी 18 के अन्तिम घंटों में एक भानुमति का पिटारा खुल गया जिसके कारण वनों को आफसेट में कार्बन बाज़ार में एक अनुपालन विकल्प के रूप में परिवर्तित किया जा सकता था

आर ई डी डी सत्यापन - विश्वस्नीयता का बोझ?

हरमीन क्लेमैन, प्रोग्राम ऑफिसर आर ई डी डी पॉलिसी, डब्लू डब्लू एफ जर्मनी

यह आर ई डी डी के लिए पहले ऊपर व फिर दो हफ्तों के लिए नीचे का समय 18वीं कॉन्फ्रेन्स ऑफ पार्टीज़ यू एन एफ सी सी सी में रहा जिसने मध्यस्थता करने वालों व निरीक्षकों दोनों को थका कर रख दिया। सात सालों में पहली बार यू एन एफ सी सी सी के तकनीकी अंग एस बी एस टी ए के अन्तर्गत कोई समझौता नहीं हो सका व आर ई डी डी की आर्थिक सहायता जो कि एल सी ए के अधीन होती है का नतीजा उसे आगे लेकर जाने के लिए भविष्य के कार्य प्रोग्रामों पर आधारित है, इसलिए यह प्रकिया पर केन्द्रित है। हालांकि देशों के इस बात को लेकर मार्गदर्शन के लिए कि कैसे स्रावों की कमी को आर ई डी डी के कार्यों के द्वारा नापा जाए (वनों का निरीक्षण, एम आर वी, रेफ्रेन्स स्तर) इसके वर्णन का सभी पार्टियों व एन जी ओ ने स्वागत किया परन्तु इसका अनुमोदन नतीजों के आधार पर धन चुकाने के लिए अर्न्तराष्ट्रीय सत्यापन की आवश्यकता के कारण असफल रहा।

जहॉं पर कई लोगों ने यह बहस की कि सत्यापन के लिए बातचीत द्वारा समझौता हुआ स्तर तभी तर्कसंगत है जब आर ई डी डी कार्बन बाज़ार का भाग बन जाए, इसलिए इसे पाने की कोशिश नही करनी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आर ई डी डी एक बहुत जटिल प्रणाली है जिसमें वन कटाव व उनकी गुणवत्ता में कमी के कारण हुए कार्बन स्रावों की बहुत जटिल जॉंच व नपाई की प्रकिया शामिल होती है। जितनी जटिल प्रकिया होगी उतनी ही विस्तृत ज़रूरत इस बात की होगी कि उसकी रिपोर्टिंग स्पष्ट हो जिसके कारण नतीजों में पर्यावरण की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित रहे। इसे सुनिश्चित करने के लिए देशों को लगातार आर्थिक मदद मिलती रहनी चाहिए व अर्न्तराष्ट्रीय विशेषज्ञ टीमों से तकनीकी मदद भी। यह आई सी ए प्रकिया के तहत किया जा सकता है व इसका स्पष्ट लिंक होना चाहिए। सी ओ पी 17 में यह पहले ही तय कर लिया गया था कि देशों को चरणवार अपने संदर्भ स्थापित कर लेने चाहिएं। यही सिद्धान्त विश्वसनीय परिणामों के प्रमाण पर भी लागू होगा। इसे हम सत्यापन या फिर अभी के लिए क्षमता निर्माण भी कह सकते हैं। साथ साथ इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है कि किसी बात पर सहमति बने क्योंकि इसमें समय लग सकता है: सत्यापन आर ई डी डी फेज़ 3 की ज़रूरत है। अधिकतर देश अभी फेज़ 2 या कुछ तो फेज 1 में भी हैं।

"इसका नतीजों के आधार पर धन चुकाने के लिए अर्न्तराष्ट्रीय सत्यापन की आवश्यकता के कारण असफल रहा"

सामान्य कार्बन बाज़ार के स्तर में अभी भी कमी - दोहा से चिंता के चिन्ह

नायोकि यामागिशी, लीडर,
क्लाइमेट एन्ड एनर्जी ग्रूप,
डब्लू डब्लू एफ जापान

पार्टियाँ अब भी कार्य प्रोग्रामों को दोहराने के चक्र में ही फँसी हुई हैं। पिछले साल की ही तरह दोहा में इस साल भी यू एन एफ सी सी सी के निर्णय ने फिर से कार्य के प्रोग्राम के नए सेट तैयार कर दिए जिनके आधार पर विभिन्न तरीकों व "नए बाज़ार पर आधारित प्रणालियों" और "ढाँचों" पर चर्चा की जाए। समझौते की बातचीत की चर्चाएँ पार्टियों की स्थिति बताने में मददगार थीं ,परन्तु केवल कागज़ पर बहुत ही कम प्रगति दिखाई देती है।

हालांकि एक "ढॉचे" का जल्दी न होने में एक खतरा भी है। क्यों? यह इसलिए कि 2012 के बाद फिर सी डी एम की जैसी राष्ट्रीय सरकारों या किसी अन्य के द्वारा बनाई गई ऑफसेट प्रणालियाँ हो जाएँगी। शायद इसका सबसे ठोस उदाहरण जापानी जॉइन्ट क्रेडिटिंग मेकेनिज़्म है (जो कि पहले बाइलैटरल ऑफसेट क्रेडिटिंग मेकेनिज़्म कहलाता था)। यह प्रचलन समस्यापूर्ण हो सकता है क्योंकि फिर वे पार्टियाँ अपनी प्रतिज्ञाओं में गैर यू एन क्रेडिट लेना शुरू कर देंगी। ऐसे क्रेडिटों के लिए पहले से ही गैर यू एन प्रणाली की कैनकुन प्रतिज्ञा (जो कि दोहा में अपनाई गई) के लिए सामान्य रिपोर्टिंग संरूप में एक सेक्शन है। इसलिए अगले सी ओ पी में हमें और ज़्यादा कठिन काम करने की आवश्यकता है ताकि सामान्य स्तर बनाए जा सकें जो कि सिस्टम की सम्पूर्ण पर्यावरण अखंडता की सुरक्षा कर सकें।

> "एक और नई प्रणाली बनाने की प्रकिया के लिए जल्दी करने का कोई कारण नहीं है जबकि क्रेडिटों की भारी आपूर्ति का अंदेशा बना हुआ है"

दोहा ने कार्बन बाज़ारों को विषाद में छोड़ा परन्तु गर्म हवा को कुछ हद तक घटाया

वुल्फगैंग स्र्टक, प्रोजेक्ट कोओरडिनेटर,
वुपरटैल इन्स्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट,
एन्वयरॉन्मेन्ट, एनर्जी

दोहा में मौसम की कॉन्फ्रेन्स में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी जिससे कि ई यू, ई टी एस व सी डी एम के गिरते हुए दामों पर रोक लगाई जा सके। ई यू अभी भी अपने लक्ष्य को 30 प्रतिशत नहीं कर पाई है जबकि उसने अपने 20 प्रतिशत के लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। सी डी एम से आपूर्ति को कम करने के लिए प्रस्तावों ने साथ साथ उसकी पर्यावरण प्रभावकारिता को सुधारा है जैसे कि बेसलाइन को मज़बूत करना या फिर उधार को एक 10 वर्षीय अवधि के लिए सीमित करना परन्तु फिर भी इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका। वे देश जिनके पास अतिरिक्त ए ए यू हैं उन्होंने सफलतापूर्वक उन प्रस्तावों को पीछे कर दिया है जिनसे प्रतिबद्धता की दूसरी अवधि (सी पी 2) पर अतिरिक्त ए ए यू होने पर उन्हें नकार दिया जाएगा।

हालांकि ए ए यू को खरीदने की संभावना पर खरीदने वाले देश को सी पी 1 में तय की गई राशि के 2 प्रतिशत सीमा लगा दी गई और सभी संभावित खरीददारों ने यह घोषित किया कि वे सी पी 1 के अतिरिक्त ए ए यू नहीं खरीदेंगे। कुछ अच्छे अचम्भित करने वाली बातों में सी पी 2 में नई गर्म हवा बनाने की संभावना को इस निर्णय के साथ समाप्त कर दिया गया कि सी पी 2 के सभी ए ए यू जो कि 2008 से 2010 के बीच के देश के औसत स्रावों से ऊपर होंगे उन्हें नकार दिया जाएगा। कार्बन बाज़ार कोई रामबाण दवा नहीं हैं परन्तु यदि आप उन्हें अपनी मौसम योजना का केन्द्र बना कर रखना चाहते हैं, जैसा कि कई देशों ने किया भी है, तो आपको कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह काम करते रहें।

> कार्बन बाज़ार कोई रामबाण दवा नहीं हैं परन्तु यदि आप उन्हें अपनी मौसम योजना का केन्द्र बना कर रखना चाहते हैं, जैसा कि कई देशों ने किया भी है, तो आपको कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह काम करते रहें।

यू एन एफ सी सी सी की लोगों की वास्तविकता से बढ़ती दूरी

डौरोथी ग्रेस एम. ग्वीरेरो,
प्रोग्राम कोओरडिनेटर क्लाइमेट एन्ड एनवायरॉन्मेन्टल जस्टिस,
फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ

सी ओ पी 18 के निराशाजनक नतीजों ने दिखा दिया है कि विकसित देशों की मौसम की संकट की स्थिति की तुरन्त ज़रूरतों को सही, नैतिक व ज़िम्मेदार तरीके से निपटाने की मंशा नहीं है। केवल इस वर्ष में ही प्रकृति ने दुनिया के कई भागों में कई ऐसी रिकार्ड तोड़ने वाली दैवी आपदाएँ दी हैं जो पहले कभी सुनी नहीं थीं। इसी तरह की दुखद घटनाएँ दोबारा भी होंगी और शायद इससे भयंकर भी। नए अध्ययनों से पता चलता है कि मौसम में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं और वह भी संसार के लिए सोचे गए कहीं गंभीर परिणामों से ज़्यादा।

पिछले चार सालों की समझौता वार्ताओं का नतीजा वह है जो कि हम आज देख पा रहे हैं - एक कमज़ोर कोयोटो प्रोटोकॉल जिसको बहुत कम देशों का समर्थन प्राप्त है व जो कि एक 'लैसे फेयर' तरीके से चल रहा है जहाँ स्राव कम करने की 2020 तक केवल "स्वैच्छिक प्रतिज्ञाएँ"ही ली जाएँगी। अन्तर्राष्ट्रीय औसत तापमान में इस शताब्दी में 4 से 6 डिग्री सेन्टीग्रेड की बढ़ोत्तरी का खतरा, विकसित देशों की कम संख्या जिन्होंने कि मौसम में बदलाव के प्रति कोई योगदान नहीं दिया को विनाश की, अधिक गरीबी की, व भविष्य में मौसम के शरणार्थी बनने की केवल ज़्यादा से ज़्यादा चेतावनी ही दी जा सकती है। इसके साथ साथ उनके वन, धरती और जल को भी बाज़ार में उतार दिया जाएगा और मौसम को बचाने के बहाने उनसे छीन लिया जाएगा।

"गरीबों ने मौसम परिवर्तन में कम योगदान दिया है, परन्तु उनके वन, भूमि और जल को बाज़ार में उतारा जाएगा और मौसम को बचाने के नाम पर वह उन्हें भी नसीब नहीं होगा"

हम कितनी और सी ओ पी करने में समर्थ हैं?

वियर्ट वियर्टसेमा, बोथ एन्ड्स

सी ओ पी 18 में कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़

पहले से कहीं ज़्यादा अब वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मानव के द्वारा बनाए गए मौसम के परिवर्तन हो रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के कारण होने वाले नुकसान व उससे होने वाली विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि (ग्लोवल वॉर्मिंग) लगातार बढ़ रही है। तब तक जब तक कि मौसम परिवर्तन का दाम ग्रीन हाउस गैसों के स्रावों के दामों में दिखाई नहीं पड़ता ये स्राव निश्चित रूप से बढ़ते ही जाएँगे। इसके साथ प्राकृतिक आपदाओं से हुए मौसम परिवर्तन के 'बिल' तो पीड़ित जनता को ही चुकाने होंगे। मौसम परिवर्तन के प्रभावों के दामों के भविष्य में निश्चित रूप से बढ़ने की ही संभावना है।

मौसम परिवर्तन पर होने वाला अगला सम्मेलन एक बार फिर से इस बात पर विचार विमर्श करेगा कि कैसे इस बदलाव को स्राव की कड़ी के अन्तिम दौर से फिर से शुरू के दौर पर लाया जाए। कड़े नियमों के अभाव में और ध्यान कड़ी के अन्तिम दौर में केन्द्रित रहने के कारण कार्बन बाज़ार इस समस्या का एक भाग बने रहते हैं। हरेक नए सम्मेलन के साथ स्रावों को कम करने के कारगर तरीकों को प्राप्त करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। स्पष्टत: यह समझना मुश्किल है कि राजनीतिज्ञ कैसे इस बात पर संतुष्टि प्रकट कर सकते हैं कि इन मीटिंगों के परिणाम सफल रहे। फिलीपींस के मध्यस्थ के द्वारा प्रचंड तूफान जिसने उनके देश में सम्मेलन के दौरान तबाही मचाई उसके संदर्भ में दिए गए भावपूर्ण भाषण इस बात को स्वयं सामने लेकर आता है: राजनैतिक यर्थाथवाद व मौसम परिवर्तन के तथ्यों के बीच का अन्तर अन्तत: कब दूर होगा? संसार को नए नेतृत्व की सख्त ज़रूरत है।

"राजनैतिक यर्थाथवाद व मौसम परिवर्तन के तथ्यों के बीच का अन्तर अन्तत: कब दूर होगा? संसार को नए नेतृत्व की सख्त ज़रूरत है"

सी ओ पी ने कार्बन बाज़ारों की कालिख को और काला किया

सौम्या दत्ता, बियॉन्ड कोपेनहैगन इन्डिया

सी ओ पी 18 में कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़

दोहा से किसी ने भी कोई खास उन्नति की अपेक्षा नहीं की थी। और एक बार फिर से कार्बन बाज़ार के बदमाश अपनी कुछ गन्दी चालों के साथ सामने आ गए। यह तय करना कठिन है कि किसे "कार्बन के काले बाज़ार" के राजा का खिताब मिलना चाहिए। भारतीय सरकार की एक "स्टेबिलाइज़ेशन फन्ड" को बनाने की योजना जो कि कार्बन बाज़ार को ढहा देगी वह इस ताज के हकदारों में से एक है। यू एन एफ सी सी के सी डी एम 2012 की वह रिपोर्ट जो कि विकासशील देशों के निर्लज्जता से "दीर्घकालिक विकास लाभों" के नकली भुगतानों को आगे बढ़ाना चाहती है, वह पूर्ण रूप से लाभ बनाने वाले निगमों के अपने आप बनाए गए ऑकड़ों पर आधारित है और उतनी ही बदनाम भी है। यह नकली भुगतानों की मॉग तब की जा रही है जब मूल अध्ययनों से यह पता चल रहा है कि सी डी एम के प्रोजेक्ट कितने दोगले हैं। पिछले दस वर्षों में अर्न्तराष्ट्रीय कार्बन बाज़ारों में स्रावों में बेचने व खरीदने वाले देशों में बढ़ोत्तरी देखी गई है। परन्तु वह अन्तिम धक्का ईनाम का हकदार है जिसके कारण समझौता बातचीत में एक विशाल व भविष्य में सर्वनाश लाने वाला कार्बन बाज़ार का बनना जिसमें कि खेती व भूमि कार्बन अधिग्रहण भी शामिल है वह आता है। एफ ए ओ के पहले के दावे के अनुसार भूमि अधिग्रहण को सबसे अधिक कम करने की क्षमता विकासशील देशों में है और यह एक राक्षसीय प्रतिद्वन्दी है। कार्बन से प्राप्त गन्दा धन खाद्य प्रभुत्ता व मानव जीवन से अधिक कीमती प्रतीत होता है।

"कार्बन से प्राप्त गन्दा धन खाद्य प्रभुत्ता व मानव जीवन से अधिक कीमती प्रतीत होता है"

दोहा: एक बाहर वाले के भीतर से विचार: मौसम सम्बन्धी बातचीत को क्यों कहीं लेकर नहीं जाया जा सका

डॉ टिम कैडमैन, यू एन यू इन्स्टीट्यूट फॉर एथिक्स गवर्नेन्स एन्ड लॉ, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी

सी ओ पी 18 में कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़

यह स्वयं सिद्ध हो चुका है कि जितनी ज़्यादा मौसम पर वार्ताऐं या सी ओ पी होंगी उतना ही नतीजा कम निकलेगा। सी ओ पी 18 जो कि दोहा में 26 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2012 के बीच हुई वह भी इसका कोई अपवाद नहीं थी। शुरूआत से ही गम्भीर माहौल रहने के कारण जो कि हॉल में प्रतिनिधियों के ऊपर एक डरावनी मकड़ी की तरह बैठा था उसे देखते ही 17000 से भी ऊपर भाग लेने वालों को यह स्पष्ट हो गया था कि उम्मीद कम ही है। यह तीसरे दिन तक पक्का भी हो गया था जब क्रिस्टीयाना फीगरीस जो कि यू एन एफ सी सी की एग्ज़िक्यूटिव सेक्रेटरी हैं उनका विचार यह था कि नागरिकों को अपनी सरकारों की ओर मौसम परिवर्तन के उपायों के लिए नहीं देखना चाहिए और उन्हें इसके लिए स्वयं कदम उठाने चाहिऐं। जो कि स्रावों के व्यापार की स्कीमों को लेकर चिंतित है, विशेषकर आर ई डी डी को लेकर, उनके लिए सबसे न्यूनतम स्तर तब रहा जब कि नॉर्वे और ब्राज़ील ने अपने कार्बन के मोल भाव के हिसाब किताब को लेकर बनाई गए सत्यापन की मज़बूत प्रणालियों (नॉर्वे) या फिर मौजूदा स्कीमों पर हाथ न लगाने वाली प्रतिक्रियाऐं (ब्राज़ील) के बीच अन्तर मिटाने में अक्षमता दिखाई। नतीजतन सारी परिचर्चाऐं थम गई और वे करोड़ों डॉलर जो कि विकासशील देशों के लिए वन कटान व उनकी गुणवत्ता में कमी (व इस प्रकार ग्रीन हाउस गैस स्रावों को कम करने) के लिए प्रोत्साहन प्रणाली बनाने के लिए लगने वाले थे वे अब संकट में हैं। मेरी अपरिहार्य विचारधारा : कॉन्फ्रेन्स में सरकारी व गैर सरकारी प्रतिनिधियों को जैसे जैसे विकास हुआ उसे सूचित करने के लिए उच्च स्तर का सहारा व ढॉचा उपलब्ध कराया गया, और यदि इस सब का सोच विचार में प्रयोग किया जाता तो शायद वह अधिक कारगर सिद्ध होता।

"सबसे न्यूनतम स्तर तब रहा जब कि नॉर्वे और ब्राज़ील ने अपने कार्बन के मोल भाव के हिसाब किताब को लेकर बनाई गई सत्यापन की मज़बूत प्रणालियों के बीच अन्तर मिटाने में अक्षमता दिखाई"

डॉ कैडमैन की पहले दिन की एक साइड इवेंट में प्रस्तुति : "आर ई डी डी : दोहा व उसके पश्चात बार बार उठने वाले मुद्दे व सुझाव" को यहाँ देखा जा सकता है
http://www.youtube.com/watch?v=UgijfyTd-4U

मेक्सिकों में हवा की ऊर्जा को काम में लाने की चुनौती - इस्थमस ऑफ त्यूहैनटेपैक का केस

इन्टर अमेरिकन असोसिएशन फॉर एन्वायरॉन्मेन्टल डिफेन्स (ए आई डी ए) व मेक्सिकन एन्वायरॉन्मेन्टल लॉ सेन्टर (सी ई एम डी ए)

मौसम परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, कम कार्बन वाले प्रोजेक्टों जैसे कि विंड फार्मो को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। परन्तु साथ साथ इसकी अत्यधिक ज़रूरत होने के बावजूद इन प्रोजेक्टों को एक दीर्घकालिक व निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। यह लेख मेक्सको व बाकी संसार के लिए स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाले प्रोजेक्टों के लिए योजना व विकास की प्रणाली सुधारने एक खुला आमन्त्रण है ताकि सभी प्रभावित समुदायों के मानवाधिकारों की इज्ज़त बरकरार रखी जा सके।

अर्न्तराष्ट्रीय निवेश की सहायता से जिसमें कि इन्टर अमरीकन डेवेलपमेन्ट बैंक से आर्थिक मदद शामिल है व कोयोटो प्रोटोकॉल के अर्न्तगत क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम) में स्थापित मेक्सिको सरकार ने कम से कम 14 विंड प्रोजेक्टों के विकास को ओएक्साका में इस्थमस ऑफ त्यूहैनटेपैक में मान्यता दे रखी है, जो कि देश का सबसे गरीब राज्य है जिसकी करीब 34 प्रतिशत से अधिक जनता स्वदेशी मूल की है। कुल मिलाकर 180 मेगा वॉट के ये विंड प्रोजेक्ट सालाना करीब 800 हज़ार मेगा वॉट से अधिक का उत्पादन करेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रोजेक्टों ने नकारात्मक सामाजिक व पर्यावरण की कीमत अर्जित की है जो कि उसके लाभों से ज़्यादा है क्योंकि इसने मानवाधिकारों व स्थानीय मूल जनता की को उनके मुफ्त पहले से सूचित कर ली गई इच्छा के अधिकार की अनदेखी की है जिससे कि उनकी ज़मीन व रोज़गार पर असर पड़ेगा। यह गम्भीर स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि मेक्सिकन सरकार ने इन निवेशों को नियंत्रित करने के लिए नियम कानून विकसित नहीं किए हैं जिसके कारण निजी कम्पनियाँ सीधे जाकर स्थानीय समुदायों से समझौते कर लेती हैं। इसके साथ साथ स्थिति निम्न कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है:

- **स्थानीय जनता को सूचना की कमी रहती है:** अधिकतर स्थानीय लोगों का कहना है कि विकासकर्त्ता प्रोजेक्ट के विषय में सम्पूर्ण व समय से जानकारी उपलब्ध नहीं कराते। उदाहरण के लिए हाल के सार्वजनिक फोरमों में रहने वाले लोगों ने यह कहा कि उन्हें प्रोजेक्टों के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में नहीं बताया गया जैसे कि वे जो अब उनके भूमि पर खेती करने को प्रभावित कर रहे हैं।
- **स्थानीय लोगों को विरोध करने पर धमकियाँ व उनके खिलाफ हिंसा** : करीब दो सालों से जिजोट और ज़ैपोटिका समुदायों ने धमकियों व उनके नेताओं के साथ पैरा मिलिटरी समूहों व सरकारी अधिकारियों के द्वारा विकास के खिलाफ विरोध करने पर हिंसा की शिकायतें की हैं।
- **मुफ्त, पहले से सूचित मंज़ूरी की कमी** : विंड के विकासकर्त्ताओं को कन्सेशन व आधिकारिक अनुमति देने की जल्दबाज़ी में मेक्सिकन सरकार स्थानीय समुदायों से चर्चा करने की अपने अनुबंध जो कि अर्न्तराष्ट्रीय कानून से बंधित है पूरी तरह से असफल रही है।
- **भूमि किराए पर देने की गैर मुनासिब शर्तें** : विंड विकासकर्त्ताओं ने स्थानीय नागरिकों से बहुत ही कम मूल्य पर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। इन लोगों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे ये बराबर के व निष्पक्ष तरीके से इसे कर सके।
- **पूरे समुदाय के लिए किसी व्यापक लाभ का अभाव** : विंड प्रोजेक्टों में एक वृहत पर्यावरण व सामाजिक विकास योजना का अभाव है और इसलिए वे केवल जनता के एक छोटे हिस्से को ही लाभ पहुँचा सकने की स्थिति में है जो कि मुख्यत: वे निवेशक और कम्पनियाँ हैं जो कि ऊर्जा को

इन्टर अमेरिकन असोसिएशन फॉर एन्वायरॉन्मेन्टल डिफेन्स (ए आई डी ए)

एक लाभ रहित पर्यावरण कानून संस्थान है जो कि अर्न्तराष्ट्रीय सीमाओं से परे खतरे में पड़े इको सिस्टमों व उन पर निर्भर मानव समुदायों की प्रतिरक्षा करता है। इसका उद्देश्य लोगों के मिलेजुले स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की क्षमता को मज़बूती प्रदान करना है जिसे वह राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय कानून के विकास व कार्यान्वन को कारगर तरीके से पालन करवा कर सुनिश्चित करता है।

www.aida-americas.org

मेक्सिकन एन्वायरॉन्मेन्टल लॉ सेन्टर (सी ई एम डी ए)

एक गैर पक्षपाती नागरिक संस्था है जो पर्यावरण के बचाव व स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को बढ़ावा देती है। इसका कार्यक्षेत्र कानून को सही तरीके से कार्यान्वित कराना, सार्वजनिक योजनाओं में सुधार, कानूनी सुदृढ़ीकरण व कानून के नियमों में मज़बूती लाना है। इसका लक्ष्य पर्यावरण के साथ एकरूपता में रहते हुए बेहतर समाज कल्याण स्थितियों को प्राप्त करना है।

www.cemda.org.mx

खरीद सकते हैं। जहाँ कि कुछ स्थानीय लोगों ने अपनी ज़मीन किराए पर दे दी हैं परन्तु ये अभी तक सच्चे विकास में परिवर्तित नहीं हो पाई हैं जैसा कि लोगों को कहा गया था।

- **पर्यावरण पर प्रभाव :** इन प्रोजेक्टों ने अत्यधिक पर्यावरणीय नुकसान किया है इसके बावजूद इन नुकसानों की भरपाई करने के लिए पहचान या बचाव के लिए कोई भी अध्ययन नहीं किए गए हैं। प्रभावों में ज़मीन के ढेर सारे भागों को जलाना (जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसों का स्राव होता है), लगाए गए पेड़ों का कटान व माइग्रेटरी पक्षियों के रहने के स्थानों को नष्ट करना शामिल है।

विंड फार्मो के विकास में सामाजिक व पर्यावरण के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए व मानवाधिकारों के हनन से दूर रहने के लिए निम्नलिखित कार्यो का सुझाव दिया गया है:

- **विंड के विकास के लिए एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जाए जो मानवाधिकारों की इज़्ज़त करे।** इस प्रोटोकॉल का सभी सार्वजनिक योजनाओं में पालन किया जाना चाहिए और इसे गुणवत्ता के सभी मानदंडों को मानना चाहिए: इसमें वे मानदंड व सूचक शामिल हों जो कि पर्यावरण व सामाजिक अवस्थाओं को पूरा करें, क्षेत्र में आर्थिक बढ़ोत्तरी को बढ़ावा दें जिसमें कि विशेषकर से गैर भूमि मालिकों को फायदा हो, निजी क्षेत्र के विकासकर्त्ताओं के बीच,स्थानीय व राष्ट्रीय सरकारों व स्थानीय समुदाय के बीच सामंजस्य बने।

- **इस बात की गारंटी हो कि सभी साझेदारों व प्रभावित जनता को प्रोजेक्ट के विषय में समय से व विस्तृत और स्पष्ट सूचना प्राप्त हो।** यह जनता का अधिकार है कि उनकी पहले से मुफ्त व सभी जानकारी से भरपूर मंशा जानी जाए जिसका अर्थ है कि उनके निर्णय को सही इज़्जत मिले चाहे वे समर्थन करें या न करें। इसके साथ साथ साझेदारों को ऐसे अवसरों की तलाश में रहना चाहिए जहाँ कि वे स्थानीय जनता को लाभान्वित कर सकें जैसे कि रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने व समुदाय के प्रोजेक्टों में।

- **ऐसी प्रकिया को कार्यान्वित व विस्तृत करना जो प्रोजेक्ट की बाह्यता को नाप सके।** इनमें मेक्सिकोज़ फेडेरल इलेक्ट्रिसिटी एन्ड हायड्रोकार्बन्स रेग्युलेटर स्वतन्त्र रूप से उसकी दीर्घकालिकता का विशलेषण करेंगे। यदि वह विश्लेषण में यह लगता है कि इस विकास से स्थानीय जनता को लाभ नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में कमीशन को बिजली की ग्रिड से इन्कार करने का पूरा अधिकार होगा।

भद्र समाज के प्रतिनिधियों के रूप में हम जो कि पर्यावरण की सुरक्षा व उस पर निर्भर समुदायों के लिए काम करते हैं इस लेख के द्वारा प्रभावित समाज की आवाज उठाना चाहते हैं। इस चेतावनी के साथ साथ हम सलाह देना जारी रखेंगे व उनके न्याय व बराबरी के लिए प्रयासों को सहारा भी देते रहेंगे।

बिसासर सड़क के गढ्ढे भराव का प्रोजेक्टः पर्यावरण के लिए खतरा

खदीजा शरीफ, सेन्टर फॉर सिविल सोसाइटीज़ के साथ अनुसंधानकर्त्ता (सी सी एस - यू के ज़ेड एन), दक्षिण अफ्रीका

जब यू एन एफ सी सी सी की एग्ज़िक्यूटिव सेकेटरी क्रिस्टीना फिगरस ने डर्बन के बिसासर मिथेन से गैस बिजली के प्रोजेक्ट को संसार के दस सबसे अच्छे ग्रीन प्रोजेक्टों में बताया तो डर्बन म्यूनिसिपैलिटी ने चैन की साँस ली। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बीता जब कि वॉशिंगटन पोस्ट की मुख्य पेज की खबर ने इस डम्प के भेदभाव के समय के मूल को उजागर किया था जिससे कि निवेशक जिसमें व्र्लड बैंक भी शामिल था वे सब डर गए थे।

एक काले लोगों की रियाइशी जगह पर बगैर किसी बफर के बनाया गया दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा औपचारिक गढ्ढा (लैन्डफिल) हर प्रकार की गन्दगी चाहे वह नाली का मलवा हो या अस्पताल का, उसे ग्रहण करता। इसे म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा हरी झंडी दे दी गई इसके शहर के पास होने की वजह से और इतने बड़े गढ्ढे के लिए उपलब्ध जगह होने के कारण। फिर भी एक समय में, अफ्रीकन नैशनल कॉन्ग्रेस जो कि देश में भेद भाव के विरूद्ध अभियान चला रही थी उसने इसे वंद करने की मुहिम चलाई क्योंकि यह पर्यावरण से भेदभाव का एक भयंकर कार्य था। दक्षिण अफ्रीका की कैन्सर असोसिएशन ने इसकी तुलना एक ऐसे परीक्षण से की जहाँ कि नागरिकों को "लैब के चूहों" की तरह प्रयोग किया जा रहा था। परन्तु लिवरेशन के आते ही और ए एन सी की हिम्मत के कारण अर्न्तराष्ट्रीय आर्थिक ढाँचे के आर्थिक सिद्धान्तों के कारण न केवल असमानता के अलग अलग तरीके मिले परन्तु एक गैर राजनैतिक तरीके का तर्क भी मिला। सरल रूप में इसे बगैर कलंक का भेदभाव कहा जा सकता है।

सी डी एम के नियमों का मज़ाक बनना सब जगह साफ दिखाई देता है। यह प्रोजेक्ट दिखाई देने वाले व छिपे हुए राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय कानून की अनदेखी करता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्स रेग्यूलेशन के सेक्शन 4.4 में कहता है कि "यह एक न्यूनतम आवश्यकता है कि गढ्ढों को उन स्थानों पर न बनाया जाए जहाँ पहले से कोई अन्य खराबी हो जिसका कि बनाते समय ही पता लग जाता है और वह जनता की सुरक्षा व स्वास्थ्य की अनदेखी न करे।"इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका में अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को दीर्घकालिक विकास में योगदान देने वाला बता कर मंजूरी दी है जो कि सभी सी डी एम प्रोजेक्टों के लिए पहली ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ बिसासर प्रोजेक्ट को सी डी एम की मंजूरी से काफी पहले ही शुरू कर दिया गया था गढ्ढों की गैस के प्रबन्धन के लिए (1996 में तो उसमें से गैस निकलने लगी थी)यह दिखाते हुए कि यह आर्थिक तौर पर लाभ देगा व साथ में पर्यावरण के लाभ भी होंगे। अपने स्वभाव के अनुसार जलने वाले प्रोजेक्ट में 90 प्रतिशत गैस स्राव होते हैं जिसमें कि केवल बिसासर में एन जी ओ जी ए आई ए के अनुसार करीब 60 प्रतिशत गँवाया है।

टडर्बन म्यूनिसिपैलिटी ने सबसे पहले इस विचार से मीथेन गैस को जलाकर शहर के लिए बिजली बनाने के लिए उपयोग करने को सोचा "परन्तु एक शहर की तरह यदि हम इससे कुछ पैसा भी बना लें तो हमें यह नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है और सब नैतिक मुद्दे प्रोजेक्ट से हट कर हैं। हमने तो सी डी एम के पहले ही यह प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। हम तो पहले ही उसी रास्ते पर चल रहे थे, हमारा

ejolt

सी एस - यू के ज़ेड एन, दक्षिण अफ्रीका सी सी एस के मेज़बान एन्वायरॉन्मेन्टल ऑर्गेनाइज़ेशनज़ का ट्रेड एन्ड लायबेलिटीज़ (ई जे ओ एल टी)का यह एक प्रोजेक्ट है। यह एक विशाल सहयोगपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि विज्ञान और समाज को एक साथ लाकर इकोलॉजिकल बँटवारे की लड़ाई को लिखित रूप देकर पर्यावरण के प्रति वेइन्साफी के लिए काम करता है www.ejolt.org खदीजा एक पत्रकार भी हैं और 'द अफ्रीका रिपोर्ट' के लिए लिखती भी हैं। उनसे kalebron@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

काम जल्दी हो गया क्योंकि आर्थिक मदद प्राप्त थी। यदि ऐसा नही होता तो हमें प्रोजेक्ट में तब तक देरी हो जाती जब तक अन्यत्र कहीं आर्थिक सहायता न मिलती..."

जबकि कम्पनी के ट्रेडिंग एमिशन पी एल सी ने नवम्बर **2008** में एक समझौते पर एक मिलियन सी ई आर खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए थे परन्तु ऐसा लगता है कि **2011** के अन्त तक भी कोई सी ई आर का व्यापार नहीं हुआ है।
उनके यह मानने के बाद भी कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाता सी डी एम या उसके बगैर भी परन्तु सैद्धान्तिक तौर पर उसे सी डी एम की मान्यता देने से नकार दिया जाता इस बात पर कि अपनी गैस को आर्थिक रूप से "सकारात्मक" दिखाने के लिए जलाया जा रहा है। दुनिया भर की कई सरकारों की तरह कई मिलियन पैसे निवेश किए जा चुके हैं जिन्हें कि सी डी एम के "पेबैक" के तथ्य के रूप में सही ठहराया गया है। यह पूछे जाने पर कि कैसे सी डी एम ने सिटी इन्वेस्टमेन्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट के द्वारा विकास में मदद की, पार्किन्स ने बताया कि "क्योंकि जब आप शहर को प्रोत्साहित कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह कमाई का ज़रिया बन सकता है और यह डूबेगा नहीं.....हमारे पास **480000** क्रेडिट पाइपलाइन में हैं और **65000** अन्य के लिए अनुमति रूकी हुई है" ट्रेडिंग एमिशन पी एल सी जैसे कम्पनियों के लिए यह गर्म हवा के इन्द्रधनुष के पार की सोने की खान हो सकता है। बाकी दुनिया के लिए ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट 'रिप ऑफसेट' की ही तरह होंगे।

जबकि किसी भी प्रोजेक्ट के पंजीकरण को रद्द करना बिसासर जैसे समस्याग्रस्त प्रोजेक्ट के लिए तर्क संगत तरीका हो सकता है जो कि मिथेन से गैस वाले प्रोजेक्ट होते हैं और जिनका अन्त गढ्ढे में जाने से होता है। यह होना तब तक संभव नहीं है जब तक बाज़ार को इकोलॉजिकल जस्टिस से बदला नहीं जाता।

पारखी नज़र!

कार्बन बाज़ार पर एन जी ओ की आवाज़

सूचनापत्र

हमारी नई वेबसाइट को देखें!

हमारी नवीनतम वेबसाइट अब अंग्रेज़ी, स्पैनिश, फ्रेन्च व चाईनीज़ में उपलब्ध है। हमें आशा है कि वह आपको पसन्द आएगी।
www.carbonmarketwatch.org
पर जाकर चेक करना न भूलें!

पारखी नज़र वालों के नेटवर्क से जुड़ें!

कार्बन बाज़ारों के विकास पर सूचित रहें, आफसेटिंग प्रोजेक्टों व उनके जनता और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के विषय में सूचनाएँ, चिंताएँ व जानकारियाँ बाँटें। एक साथ मिलकर हम लोग नुकसानदायक प्रोजेक्टों और प्रणालियों का खुलासा करने की लड़ाई जारी रखेंगे। सभी एन जी ओ, शिक्षाविदों व प्रतिभागियों का स्वागत है। Network Registration. इस लिंक पर जाकर पंजीकरण कराएँ।

हमारा सी ओ पी 18 में काम देखें!

सी ओ पी 18 के दूसरे सप्ताह में कार्बन मार्केट वॉच ने प्रतिनिधियों को गर्म हवा से निपटने के लिए दो कार्य आयोजित किए। अन्त में हमने टाइटैनिक पोकर का यह खेल जीत ही लिया और कुछ हद तक गर्म हवा नियन्त्रित हुई। इसका वीडियों यहाँ here व यहाँ here देखें। इसकी फिल्मिंग करने के लिए हम आर ए सी फ्रॉस व ग्रीन्स/ई एफ ए के गठबन्धन का धन्यवाद करते हैं।

कार्बन मार्केट वॉच के विषय में

कार्बन मार्केट वॉच कार्बन बाज़ारों के विकास पर एक निष्पक्ष विचारधारा प्रस्तुत करता है और पर्यावरण व सामाजिक निष्ठा को मज़बूत बनाने की वकालत करता है। कार्बन मार्केट वॉच की स्थापना नवम्बर 2012 में सी डी एम वॉच के कार्यों को सी डी एम से आगे लेकर जाने के लिए की गई।

कार्बन मार्केट वॉच नेटवर्क अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर व दक्षिण तक फैले एन जी ओ व शिक्षाविदों को जोड़ता है ताकि कार्बन आफसेट प्रोजेक्टों के विषय में जानकारी व चिंताओं को आपस में बाँटा जा सके। इसका लक्ष्य भद्र समाज की आवाज को कार्बन बाज़ार के विकास में मज़बूती प्रदान करना है।

पर जाकर नेटवर्क से जुड़ें!

पारखी नज़र के लिए आवेदन निम्न पर ईमेल करके करें!
antonia.vorner@carbonmarketwatch.org

ट्विटर पर हमसे यहाँ जुड़ें
ट्विटर का हायपर लिंक
फेसबुक का हायपर लिंक

कार्बन मार्केट वॉच
Rue d'Albanie 117
1060 ब्रूसेल्स, बेल्जियम

info@carbonmarketwatch.org
www.carbonmarketwatch.org

डिस्क्लेमर: इस पत्रिका में रखे गए विचार लिखने वालों के अनुभव व ख्यालों पर आधारित हैं। अनिवार्य रूप से वे कहीं भी सम्पूर्ण कार्बन मार्केट वॉच नेटवर्क के मत व ख्यालों को नहीं दर्शाते।